

नगर निगम की लड़ाई के जरिए जयपुर की कांग्रेस में वर्चस्व साबित करने की होड़

इस जंग में जयपुर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी दाव पर है

जयपुर, (का.प्र.) जयपुर जिला कांग्रेस में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है और पिछले दिनों जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो दौड़ शुरू हुई थी, वह वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुकी है। जिलाध्यक्ष की यही लड़ाई अब नगर निगम की समितियों के जरिए लड़ी जा रही है। हालांकि जयपुर के विधायकों में जयपुर नगर निगम हेरिटेज में समितियां बनाने को लेकर बातचीत का रास्ता तो निकाला गया है, लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि इसके जरिए अब लड़ाई बेहद दिलचस्प होती दिख रही है।

पिछले दिनों काबीना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस तरह से निर्दलीय पार्षदों को लेकर हथकड़ी लगाई है, वह भी उसी लड़ाई का हिस्सा है। एक ओर तो जयपुर में कांग्रेस सरकार में पिछले तीन साल से जयपुर के एकमात्र काबीना मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि महापौर को निर्दलीय पार्षदों की बात सुननी पड़ेगी और महापौर का पद कांग्रेस के चेहरे पर मिला है, खुद के चेहरे पर नहीं। यहां वे महापौर को निशाना बनाते हैं लेकिन दूसरी ओर सवाल यह उठ रहा है कि जिस महिला को पार्षद का टिकट

खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया था, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सार्वजनिक रूप से खाचरियावास को उसी अपने क्षेत्र की पार्षद के महापौर बनने के बाद शिकायतें होने लगी हैं।

दूसरी ओर इस लड़ाई का एक हिस्सा हाल ही काबीना मंत्री बने महेश जोशी हैं। महेश जोशी भी अपने नजदीकी समर्थक को जयपुर का अध्यक्ष बनाने को लेकर दिल्ली तक जा चुके हैं। अब लड़ाई इस बात की है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज और जयपुर नगर निगम ग्रेटर दो हिस्सों में बांटने के बाद जयपुर के दो जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं। ऐसे में अब महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास दोनों के ही विधानसभा क्षेत्र जयपुर हेरिटेज में आते हैं। अब दोनों नेता चाहते हैं कि जो भी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष जयपुर हेरिटेज में बने, वह उनका समर्थक हो।

अब यह लड़ाई सीधी नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसे में नगर निगम की लड़ाई को माध्यम बनाया गया है। माध्यम इस तरह से कि प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि 1 साल होने के बावजूद नगर निगम की समितियां नहीं बनी, तो सवाल यह उठता है, जो खुद कांग्रेसजन

■ **जयपुर में दो काबीना मंत्रियों में वर्चस्व की लड़ाई रोक रही है निगम समितियों का गठन, पार्षदों का मनोनीयन**

■ **खाचरियावास निर्दलीय पार्षदों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, तो महेश जोशी चुप्पी साधे इंजागर में हैं**

पूछते हैं कि आखिरकार समितियां बनाने से रोक किसने है। सरकार कांग्रेस की, नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस का, चार विधायक कांग्रेस के, तो फिर आखिरकार इन निगम की समितियों के आड़े कौन आ रहा है। जबकि दूसरी ओर जयपुर ग्रेटर निगम बोर्ड का गठन होने के कुछ दिनों बाद ही समितियों का गठन कर दिया गया था। ऐसे में जयपुर के कांग्रेसजनों की उंगलियां दोनों काबीना मंत्री और दो विधायकों पर ही उठती है

कि इनमें एक राय नहीं होने का खासियाज नगर निगम के पार्षदों को भुगतना पड़ रहा है और समितियों का गठन नहीं होने से कार्यों का बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस के साथ में 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। अब यह सभी अपने लिए चेरमैनशिप मांग रहे हैं लेकिन यदि इन सभी को चेरमैन बना दिया जाता है तो फिर कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आने वाले पार्षद क्या इन सभी को स्वीकार कर लेंगे। इस उधेड़बुन का नतीजा है कि नगर निगम में समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है।

कांग्रेसजनों का सवाल तो यह भी है कि जयपुर राजस्थान में सरकार की ओर से मनोनीत होने वाले पार्षद बनाए जा चुके हैं तो आखिरकार क्या कारण है कि जयपुर के 2 नगर निगमों में अभी तक पार्षदों का मनोनीयन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे भी इन विधायकों की आपसो तनाव की स्थिति को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल जयपुर में कांग्रेस के जीते हुए विधायक अपने ज्यादा समर्थकों को मनोनीत पार्षद बनाना चाहते हैं। वहीं हर विधायक चाहता है कि उसके क्षेत्र से ज्यादा

चेयरमैन बने। यह लड़ाई भी नगर निगम में हिस्सेदारी बांटने से रोक रही है।

अब क्योंकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला आने वाले दिनों में होना है, तो नगर निगम के जरिए दोनों काबीना मंत्री अपना वर्चस्व साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि यह सही है कि पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में महेश जोशी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं। इसका कारण यह है कि महेश जोशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे विश्वस्त नेताओं में माने जाते हैं। वहीं कभी सचिन पायलट के नजदीकी माने जाने वाले और बाद में मुख्यमंत्री के नजदीक आ गए प्रताप सिंह खाचरियावास अपना मंत्री पद तो बचाने में सफल रहे, क्योंकि फेरबदल में किसी मंत्री को नहीं हटाया गया, लेकिन उनके विभाग के बंटवारे में स्पष्ट हो गया कि वह अब पहले की तरह जयपुर में ताकतवर नहीं रहे। ऐसे में अब एक बार फिर जयपुर में नगर निगम की समितियों और जयपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की लड़ाई में वर्चस्व साबित करने के लिए अपनी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि इस वर्ष की लड़ाई में शह-मात का खेल कहाँ तक जाता है।

रामू शर्मा के नेतृत्व में बांटे सचिन पायलट के फोटो छपे शॉल



प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए राजस्थान राज्य पंचायत परिषद के संयोजक रामू शर्मा ने गरीब, असहाय और फुटपाथ पर खुले में गुजर-बसर करने वाले लोगों को शॉल वितरित किए। उन्होंने इस सहायता के माध्यम से पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के प्रति अपना समर्थन भी जताया है। उन्होंने मंगलवार को सांगानेर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फुटपाथ पर रहने वाले करीब 2100 लोगों को सचिन पायलट की फोटो छपी शॉल वितरित की, ताकि वो लोग इस शीतलहर में ठंड से बच सकें। इस दौरान उनके साथ जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व महामंत्री नीतू सैनी, कांग्रेस कार्यकर्ता गुड्डि पंडित, वार्ड 81 से पार्षद जय वशिष्ठ और राजजीलाल आदि भी मौजूद थे।

दस महीने में ही गणगौरी अस्पताल के अधीक्षक को हटाया

इससे पहले जनस्वास्थ्य निदेशक के.के. शर्मा व औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा को भी बदला गया था

जयपुर, (का.सं.) चिकित्सा विभाग में पूर्व चिकित्सा मंत्री के निर्णयों को बदलने का काम लगातार जारी है। इसके तहत उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों में अहम पदों पर की लगाए गए अधिकारियों और डॉक्टरों अब हटाने का सिलसिला जारी है।

विभाग के नए मंत्री परसादी लाल मीणा ने कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मंत्री डॉ.रघु शर्मा की अधिकारों को हटा दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को गणगौरी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. रामबाबू शर्मा को भी महज दस महीने में ही पद से हटाया गया है। डॉ. रामबाबू शर्मा के स्थान पर कांठिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एल. हर्षवर्धन को लगाया गया है और उन्हें कांठिया अस्पताल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

चर्चा है कि गत सप्ताह चिकित्सा निदेशालय में शर्मा पदों में हट्टु बदलाव के बाद डॉ. रामबाबू शर्मा की विदाई तयमानी जा रही थी। चिकित्सा महकम में उनका हटाए जाने को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। बताया जा रहा है कि डॉ. शर्मा को इस पद पर जलदाय मंत्री महेश जोशी की सिफारिश पर लगाया गया था, वहीं

■ **चिकित्सा विभाग में पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्णयों को बदलने का सिलसिला जारी**

के बाद भी मरीजों को वितरित नहीं किए जाते और उन्हें बाहर दुकानों से नेपकीन लाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मामले में जांच के लिए कमेटी भी बनाई थी और उसकी रिपोर्ट में डॉ. रामबाबू शर्मा को दोषी माना गया था। इस मामले में ही उन्हें हटाया गया है।

मेरी कोई गलती नहीं : डॉ. रामबाबू शर्मा

वहीं डॉ. रामबाबू का कहना है कि इस मामले में मेरी गलती बताई जा रही है उसमें तो मेरा कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। नेपकीन देने का काम अस्पताल के गायनिक विभाग का है, इसमें चिकित्सा अधीक्षक क्या काम करेगा।

गौरतलब है कि इससे पहले चिकित्सा मंत्री ने गत सप्ताह ही जनस्वास्थ्य निदेशक के.के. शर्मा को हटाकर उनके स्थान पर वी.के. माथुर को लगाया था। साथ ही उसी दिन औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के स्थान पर अजय फाटक की नियुक्ति की थी। ये दोनों ही अधिकारी पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के नजदीकी माने जाते थे।

प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या नौ हजार से ऊपर ही बनी हुई है

राज्य में मंगलवार को 9711 नए संक्रमित मिले, इससे पहले सोमवार को 9236 रोगी पाए गए थे

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले कई दिनों से नौ हजार से ऊपर बनी हुई है। मंगलवार को राज्य में थोड़ी और वृद्धि के बाद 9711 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस बीच सात हजार से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं।

इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का व्यापक असर देखा जा रहा है। राज्य के 33 जिलों में फिलहाल कोरोना के 69 हजार 388 सक्रिय मरीज मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 19 हजार 686 रोगी जयपुर जिले में हैं। वहीं अलवर में 6169, जोधपुर में 4851, उदयपुर में 4065, बीकानेर में 3145, कोटा में 3123, भरतपुर में 3122, बाड़मेर में 2341, पाली में 2247 और अजमेर में 2201 तथा शेष जिलों में इससे कम सक्रिय मरीज हैं।

प्रदेश में मंगलवार को 9711 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले सोमवार को 9236 रोगी पाए गए थे। राज्य में पिछले कई दिनों से नए संक्रमितों की संख्या 9 हजार के ऊपर ही बनी हुई है। इधर राजधानी जयपुर में आज कुछ और मामले बढ़ने के साथ 2358 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 801, उदयपुर में 677, पाली में 569, अलवर में 568, कोटा में 563, भरतपुर में 536,

- **राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 2358 नए संक्रमित मिले हैं।**
 - **जोधपुर में 801, उदयपुर में 677, पाली में 569, अलवर में 568, कोटा में 563, भरतपुर में 536 और हनुमानगढ़ में 426 नए मरीज सामने आए हैं।**
 - **दुखद बात यह है कि पिछले चौबीस घंटों में राज्य में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हो गई है।**
- हनुमानगढ़ में 426, चित्तौड़गढ़ में 380, बीकानेर में 358, अजमेर में 270, चूरु में 252, बाड़मेर में 239, सर्वाई माधोपुर में 205 और सीकर में 204 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रतापगढ़ में 125, टोंक में 121, जैसलमेर में 117, धौलपुर में 115, बारां में 101, झालावाड़ में 94, भीलवाड़ा में 90, दौसा व नागौर में 85-85, श्रीगंगानगर में 84, सिरोंही में 68, बूंदी में 53, डूंगरपुर में 47, खूंखूर 38, राजसमंद में 31, जालौर में 25, करौली 17 और बांसवाड़ा में 9 नए मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 10 लाख 56 हजार 606 संक्रमित मिल चुके हैं। इधर राज्य में पिछले 4-5 दिन से रिकवरी में सुधार हो रहा है। इसके चलते मंगलवार को 7 हजार 56 और मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9 लाख 78 हजार 199 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुखद बात यह है कि

जनजाति बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्रों का हो सर्वांगीण विकास : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.) राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजाति बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें तात्कालिक और दीर्घकालिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के सभी परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार की सुविधा का सुरक्षा कवच प्रदान किए जाने की भी आवश्यकता जताई। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण कार्य में तेजी लाते हुए योजना से नहीं जुड़ पाए परिवारों को जल्द से जल्द पंजीकृत किए जाने पर भी जोर दिया।

मिश्र मंगलवार को राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति विकास एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति एवं समस्याओं के संबंध में विशेष समीक्षा बैठक में ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में वंचित समूहों को हर सम्भव सहायता प्रदान किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों की कोचिंग, शिक्षा छात्रवृत्ति समय पर मिले, इसकी व्यवस्था प्रभावी रूप में सुनिश्चित हो।

उन्होंने छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान की ऐसी आदर्श व पारदर्शी व्यवस्था अपनाए जाने पर जोर दिया जिसमें यथासंभव वित्त वर्ष समाप्त होने के साथ ही राशि विद्यार्थी के खाते में जमा हो जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन पत्र को कमी या त्रुटि हो तो



उसे निरस्त करने के स्थान पर उसकी पूर्ति करवाया शीघ्र विद्यार्थी को लाभाण्वित करने का प्रयास होना चाहिए।

राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों के समग्र विकास के लिए योजनाओं का व्यावहारिक क्रियान्वयन किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि नवाचार अपनाते हुए ऐसे स्थानों पर अधिकाधिक आदर्श गांव बनें। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को सी.एस.आर. के तहत उच्च पदों पर चयन के लिए बेहतर से बेहतर कोचिंग सुविधा दिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र के 5 हजार 696 गांवों में से 49 गांवों को मॉडल विलेज बनाने के बारे में जिलेवार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के केंपनी का मालिक शंकर शर्मा हैं, जोकि शाम को छुट्टी होने के बाद कार्यालय में रोककर दुष्कर्म करता था। वह तभी से देहशोषण करता आ रहा है। कुछ दिन पूर्व पीड़िता ने इसका विरोध किया तो शंकर शर्मा ने उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल कराया गया है।

सड़क सीमा में बनी 9 दुकानों और दो अवैध कॉलोनिनों पर गरजा जेडीए का बुलडोजर

कालवाड़ रोड पर खंडाका हॉस्पिटल के सामने “राधा विहार-5” और सरदारपुरा गांव में “रामेश्वर धाम” के नाम से 4-4 बीघा कृषि भूमि पर काटी गई थी अवैध कॉलोनी

जयपुर (का.सं.) जेडीए के बुलडोजर मंगलवार को सड़क सीमा में बनी 9 अवैध दुकानों और दो अवैध कॉलोनिनों में गरजा। कालवाड़ रोड पर खंडाका हॉस्पिटल के सामने “राधा विहार-5” तथा सरदारपुरा गांव में “रामेश्वर धाम” के नाम से अवैध कॉलोनी काटी गई थी। जल्द ही यहां प्लॉट बेचकर बिल्डर फरार होने की फिराक में थे। दोनों कॉलोनिना 4-4 बीघा कृषि भूमि पर काटी गई थी।

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि हाथोज-लालचंदपुरा लिंक रोड पर पीथावास में खसरा नम्बर 213/3 में रातोरात टीनशेड डालकर 9 अवैध दुकानें बना ली गई थी। जो कि प्रस्तावित 60 मीटर सेक्टर रोड की सीमा में थी। इन्हें गत 10 जनवरी को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने को कहा था, इसके बावजूद दुकानों पर टीनशेड और शटर डाल लिया गया था। इस पर मंगलवार को जेसीबी की मदद से इन्हें ध्वस्त किया है।

इसी प्रकार कालवाड़ रोड पर ही खंडाका हॉस्पिटल के सामने करीब 4 बीघा निजी खातेदारी की जमीन पर “राधा विहार-5” के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी तैयार करके यहां प्रेवल रोड व निर्माण कार्य कर लिये गये थे। पहले भी दो बार यहां पर अवैध निर्माण



जेडीए टीम ने मंगलवार को हाथोज-लालचंदपुरा लिंक रोड पर सड़क सीमा में बनी 9 दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया।

ध्वस्त किये जा चुके हैं, इसके बावजूद बाण्डूवाला, मकान व अन्य अवैध निर्माणों भूमाफिया पुनः निर्माण कर लेते हैं। मंगलवार को ध्वस्त किया है। इसी प्रकार रोज दा रोड को इस अवैध कॉलोनी में बनी प्रेवल रोड, ग्राम सरदारपुरा में भी करीब 4 बीघा निजी

■ **बिल्डरों ने ना तो कृषि भूमि का रूपांतरण करवाया और ना ही जेडीए से कोई परमिशन ली, फिर भी 4-4 बीघा जमीन पर काट रखी थी यह कॉलोनिना**

खातेदारी की जमीन पर “रामेश्वर धाम” के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए निर्माण कर लिये गये थे, इन्हें भी हटाया है। कायतकार ने ना तो भू-रूपांतरण कराया और ना ही कॉलोनी बसाने की कोई इजाजत जेडीए से ली थी। ऐसे में अब दोनों निजी खातेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोन उपायुक्त-12 को पत्र लिखा गया है। अवैध कॉलोनी बसाने वाले वाली सोसायटी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहकारिता रजिस्ट्रार को पत्र लिखा जायेगा। इसके अलावा न्यू आदिश मार्केट मेट्रो स्टेशन के पास भी द्रव्यवती नदी के किनारे 40 फीट सेक्टर रोड सीमा में आ रहे करीब 2 किलोमीटर तक 6 टिनशेडनुमा कमरे, 3 ओवरी, 3 बाण्डूवाला, पिन्सर, लोहे-लकड़ी की 6 थडियों समेत कई अवैध निर्माण हटाये गये हैं।

इस माह के अंत तक छह प्रधान खनिजों की नीलामी प्रक्रिया होगी शुरू : डॉ. अग्रवाल

जयपुर, (का.सं.) अतिरिक्त मुख्य सचिव माईस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि इस माह के अंत तक कॉपर, मेनेसाइट, लाईमस्टोन, मंगनीज और गारनेट के छह प्रधान खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस समय एक कॉपर व छह लाईम स्टोन प्रधान खनिजों की ई नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस साल राज्य में खनिज क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।

एसीएस माईस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

माईस विभाग की वर्युअल बैठक ले रहे थे। बुन्दुर्ख व नागौर के दो दो लाईम स्टोन ब्लॉकों का नीलामी नोटिस जारी किया जा चुका है और 24 जनवरी से 28 जनवरी के दौरान इस चारों ब्लॉकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह से एक कॉपर व दो लाईम स्टोन ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है और आगामी 7 से 9 फरवरी के दौरान इन ब्लॉकों की भी भारत सरकार के ई नीलामी पोर्टल पर नीलामी होगी।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय-समय पर आयोजित माईस विभाग की

समीक्षा बैठकों में खनिज खोज व खनन गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री गहलोत खनन क्षेत्र से जुड़े उद्योगियों से भी समय-समय पर रूबरू होते हुए फीडबैक लेते रहे हैं। उन्होंने बताया कि खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया नियमित रूप से विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। खनन क्षेत्र में यह वर्ष विशेष उपलब्धियों का वर्ष था। उन्होंने बताया कि खनन गतिविधियों में और अधिक तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार की संबंधित संस्थाओं से भी समन्वय बनाया हुआ है जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।